चतुर्थ अ० भा० अधिवेशन

चण्डीगढ़

१०, ११ अप्रैल — १९७१

नैशनल आँरगेनाइजेशन आँफ बैंक वर्कज

(N.O.B.W.)

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

महामन्त्री भारतीय मजदूर संघ

नैशनल ऑरगनाईजेशन आफ बैंक वर्कर्ज

(N.O.B.W.)

के

चतुर्थ अधिवेशन के अवसर पर

श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी [एम० पी०]

महामन्त्री अखिल भारतीय मजदूर संघ

का

भाषण

(N.O.B.W.)

प्रकाशक —
महा मन्त्री,
पंजाब बैंक वर्कज़ ऑरगनाईज़ेशन
बास्को बिलडिंग, जालन्धर ।

मूल्य ५० पैसे

मुद्रक
भारतीय इलैक्ट्रिक प्रेस
४-शिवाजी पार्क जालन्धर ।

— निवेदन —

इस पुस्तक में नैशनल आरगनाईज़ेशन आफ बैंक वर्कर्ज (N.O.B.W.) के १०-११ अप्रैल, १९७१ को चण्डीगढ़ में हुए चतुर्थ अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी एम० पी० द्वारा दिया गया भाषण प्रस्तुत है।

पुस्तक का उद्देश्य

बैंक कर्मचारी सम्बन्धी अपनी मूल नीति पर प्रकाश डालना है। आशा है इस पुस्तिका से उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

—राजकृष्ण भक्त

चन्डीगढ़-दिनांक ११-४-७१

आज आप सब बन्धुओं के बीच खुद को पाकर बड़ी खुशी हो रही है इस द्वीदिवसीय अधिवेशन में आप ने बैंक कर्मचारिओं के सम्मुख उपस्थित समस्यायों पर विचार किया, उनके विषय में मार्गदर्शन देने वाले प्रस्ताव पारित किए, अपनी अगली कार्यवायी की दिशा भी निश्चित की, राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिषद् (एन॰ ओ॰ बी॰ डब्ल्यू) के संगठन को अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से भी विचार विर्मश किया तथा कुछ निर्णय भी लिए। इन सब बातों को ख्याल में रक्खें तो यह कहा जा सकता है कि कम से कम समय में आप ने ज्यादा से ज्यादा काम किया है। इस सफलता के लिए आप का अभिनन्दन करता हूं।

किन्तु इस अधिवेशन में सब से महत्वपूर्ण बात वह हुयी जो किसी भी औपचारिक कार्यवाही-रिजस्टर में दिखाई नहीं देगी। औपचारिक बैठकों के अलावा बिल्कुल औपचारिक ढंग से हम काफी समय तक एक दूसरे से मिले और सब ने मिल कर पारिवारिक जीवन के आनन्द का अनुभव किया। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपना यह भारतीय मजदूर संघ केवल एक केन्द्रीय श्रम संगठन मात्र ही नहीं है। हम केन्द्रीय श्रम संस्था तो हैं ही किन्तु एक तो कई संस्थाओं में से एक, यह हमारी भूमिका नहीं। देश में कई केन्द्रीय श्रम संस्थाए हैं, उन में से एक भारतीय मजदूर सघ भी है। इतना ही केवल नहीं, अपना यह संगठन अपनी कई विशेषताओं के कारण अपने ढंग का अनोखा ऐसा केन्द्रीय संगठन है। दूसरी बात यह है कि अन्य लोगों के समान हम केवल केन्द्रीय श्रम संस्था नहीं, वह कार्य तो हम सक्षमता से कर ही रहे

है किन्तु उसके अलावा हम राष्ट्रवादी कार्यकर्त्ताओं का एक विशाल परिवार भी हैं और यही हमारा सच्चा स्वरूप है।

अपने कार्य का स्वरूप पारिवारिक है। हम केवल विधान के आधार पर कार्य नहीं चला रहे। जो विधान के सहारे कार्य चलाते हैं वे विधान के ही बोझ के नीचे दब कर खत्म हो जाते हैं। विधान हमारा मालिक नहीं गुलाम है। विधान यह साध्य और हम सब लोग उसके साधन यह विचार गलत है। हमारा आधार पारिवारिकता का भाव है उसी के सहारे मजदूर संगठन हम खड़ा कर रहे हैं। हां, परिवार में भी कुछ व्यवस्था हुआ करती है वैसी हमारे यहां भी है। उसी को लिपिबद्ध किया गया। किन्तु वह विद्यमान व्यवस्था का विवरण मात्र है। इसी पारिवारिकता के कारण ही हम लोग जब कभी एकत्रित होते हैं तो सभी को आनन्द आता है। महत्वपूर्ण औपचारिक कार्यवाही के कारण नहीं किन्तु अनौपचारिक ढंग के परस्पारिक सम्पर्क के कारण। इस तरह का स्मपर्क और पारिवारिक वायुमंडल है। सब दो तीन दिन तक अनुभव कर सकें यही सब से श्रेष्ट उपलब्धि है।

बोनस, पदोन्नति नीति (Promotion Policy) आदि के विषय में आप ने अपनी भूमिका स्पष्ट की उन सब विषयों की गहरायी में जाने की आवश्यकता अब नहीं। विभिन्न विषयों पर बैंक कर्मचारियों का मार्ग दर्शन करने की क्षमता एन० ओ० बी० डब्ल्यू में है, यह बात सभी जानते हैं और इसके कारण ऊपर से आप की दुश्मनी करने वाले लोग भी अन्दर राह देखते रहते हैं कि उपस्थित समस्यायों पर आप का अभिप्राय क्या है। आप के मार्ग दर्शन की प्रतीक्षा न केवल आप के सदस्य अपितु बाहर के बैंक कर्मचारी भी कर रहे हैं। जिस गहरायी में जा कर सूक्षमता के साथ आप ने निर्णय लिए हैं उसको देखने से मुझे विश्वास हो रहा है कि इस वर्ष भी सभी बैंक कर्मचारियों को सही नेतृत्व देने का कार्य आप

योग्यता के साथ करेंगे ।

एक समस्या का विशेष निदेश आवश्यक है । राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्यवस्थापक मंडल पर बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को लेने की दृष्टि से शासन द्वारा निदिष्ट आज की पद्धति किस तरह सदोष है यह आप ने दिखाया है । व्यवस्थापक मंडल में प्रतिनिधित्व के लिए बैंक कर्मचारियों को गुप्त मतदान पद्धति से मतदान तथा निर्वाचन करने का अधिकार प्राप्त हो यह मांग आप ने स्पष्ट शब्दों में रक्खी है । इसी को लेकर आगे बढ़ना है यही बात बैंक कर्मचारियों के हित में है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आप के प्रतिनिधियों के नाते कुछ बैंक कर्मचारी व्यवस्थापक मंडल में शामिल किए गए तो उसके फल स्वरूप बैंक कर्मचारियों या आम जनता को कुछ लाभ होगा । परिस्थिति का सर्वांगीन विचार किया तो यह विचार में आता है कि आज की अवस्था में बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के रूप में कोई भी वहां बैठे तो उसके कारण कोई परिवर्तन आने वाला नहीं बैंकिग उद्योग के विषय में हमने एक मौलिक सुझाव दिया था । वह यानी स्वायत वित्तीय निगम (Autonomous Mcnetary) के निर्माण का । यह बात मानने के लिए सरकार तैयार नहीं । राष्ट्रीय कृत बैंकों को चलाने के विषय में अभी तक कोई निश्चित नीति सरकार नहीं बना सकी और सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो आशाएं जन साधारण के मन में निर्माण की गयीं थीं उनकी पूर्ति करना निश्चित नीतियों के अभाव में किसी के लिए भी असम्भव है । इस अवस्था में किसी भी संस्था का व्यक्ति व्यवस्थापकमंडल में समाविष्ट किया गया तो भी वह अपने कर्मचारी बन्धुओं के और जनता के कल्याण को दृष्टि से अपने पद का उपयोग नहीं कर सकेगा । परिणाम स्वरूप थोड़े ही दिनों में उसे बदनामी लेकर निवृत्त होना पड़ेगा अतः व्यवस्थापक मंडल पर जाना यह एक प्रतिष्ठा का लक्षण नहीं माना जा सकता उलटी बात हो सकती है । ए० आइ० बी० ई० ए० के प्रतिनिधि वहां रहते हैं, किन्तु सामान्य कर्मचारियों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर

सकते । यही दृश्य हमारे लिए अधिक लाभदायक होगा।

विरोधी दल के नाते कर्मचारियों की प्रतिनिधिक आवाज हम समय समय पर उठाते रहे और समस्याओं के विषय में उन्हें सही मार्ग दर्शन देते रहें तो इसके कारण कर्मचारियों का हित भी अधिक सिद्ध होगा और एन० ओ० बी० डब्ल्यू की शक्ति भी बढ़ेगी। मध्यावधि-चुनाव के पश्चात राष्ट्र पति महोदय ने तथा सत्तारूढ़ सरकार ने सभी मजदूर संस्थाओं को आह्वान किया है कि औद्योगिक शांति तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करें। हम राष्ट्रवादी होने के कारण इस आह्वान को समुचित तथा सक्रिय प्रोत्साहन देना चाहते हैं फिर सत्तारूढ़ दल ने गरीबी हटाने के विषय में जो आश्वासन दिए हैं उनके कारण तो सहयोग देने की इच्छा और भी बलवान हो रही है। किन्तु पिछले दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुईं कि जिन के कारण सरकार के हेतु की विशुद्धता के विषय में संदेह निर्माण होता है। राज्य सभा के पिछले सत्र में बोनस के बारे में एक प्राइवेट बिल आया था, बोनस की न्यूत्तम राशि 4 प्रतिशत से $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत की जाए यह प्रमुख बात उसमें थी। उस समय अनोपचारिक तौर पर शासक दल के नेताओं ने मान लिया था कि वे बिल सैलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, किन्तु इस सत्र में दोबारा वह बिल जब चर्चा के लिए आया तो श्रम मन्त्री महोदय ने इस प्रस्ताव का सीधा विरोध किया और बताया कि बोनस का न्यूनत्तम दर बढ़ाने के पक्ष में सरकार नहीं है। उसके लिए जो तर्क उन्हों ने दिए वह सारे ठीक वही थे जो कि मालिकों की अखिल भारतीय संस्था ने अपनी प्रकाशित पुस्तिका में दिए थे। यह देखकर सभी को आश्चर्य और दु:ख हुआ।

इसी समय परिवार पेन्शन के विषय में बिल आया, वास्तव में परिवार पेन्शन योजना सरकार लागू करेगी इस घोषणा का हम लोगों ने स्वागत किया था। किन्तु यह देख कर आश्चर्य हुआ कि अभी जो उसका

स्वरूप है उसमें योजना के लिए मजदूरों के पैसे का भी कुछ अंश कटने वाला है जो कि उसका प्रावीडैन्ट फन्ड में कटता था। वास्तव में पद्धति यह है कि परिवार पेन्शन योजना का बोझ सरकार को ही उठाना चाहिए, चाहे तो इस कार्य में सरकार सम्बन्धित मालिकों से सहायता प्राप्त कर सकती है। किन्तु मजदूरों का पैसा इस योजना के लिए काटा जाना बिल्कुल ही गलत है। खैर यह गलत काम तो सरकार ने किया और उसके साथ प्रावीडैन्ट फन्ड योजना के विषय में जो रचनात्मक सुझाव दिए गए उनको भी सरकार ने अस्वीकार किया। यह दोनों घटनाएं हमारे मन में सरकार के इरादों के विषय में शंका पैदा करती हैं।

और अब मान्यवर अर्थमन्त्री श्री यशवन्त राव चह्वाण की घोषणा आयी है कि आगामी दिनांक २४ अप्रैल, ७१ को वह बैंकिंग उद्योग तथा बैंक कर्मचारियों के सम्मुख जनता का मांग-पत्र प्रस्तुत करने वाले हैं। दुनियां के इतिहास में इस प्रकार का कार्य यह पहली बार किया जा रहा है। प्रस्थापित सरकार, कर्मचारियों के सम्मुख ऐसा मांग पत्र (Charter of Demands) पेश करे यह बात अब तक कहीं पर भी कभी नहीं हुई। यह कहना कठिन है कि श्री चह्वाण का यह पग क्रांन्तिकारी है या हास्यास्पद। जिस जनता का वह चार्टर है उनमें क्या बैंक कर्मचारी शामिल नहीं? जनता का मन क्या बैंक कर्मचारी नहीं जानते? उनकी इच्छाओं के विषय में श्री चह्वाण की तुलना में बैंक कर्मचारियोंकी जानकारी क्या कम है? सरकार के नाते श्री चह्वाण बैंक कर्मचारियों से अनुशासन पालन के लिए औद्योगिक शान्ति तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए अपील करें यह बात तो समझ में आ सकती है किन्तु कर्मचारियों के सामने वे चार्टर पेश करें यह कार्यवाही अनोखी है। वास्तव में जनता का एक अंश के नाते बैंक कर्मचारी भी अर्थ मन्त्री जी को पूछ रहे हैं कि हमारे मांग-पत्र का क्या हुआ। पिछले चुनाव में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जो एक २ बैलट पेपर मतपेटी में डाला गया वे जनता के द्वारा शासन को प्रस्तुत किया हुआ मांग पत्र ही था। लोगों ने

किसी दल को वोट नहीं दिया, किसी व्यक्ति को नहीं दिया। लोगों ने स्वयं अपनी आकांक्षाओं को ही दिया है जिनकी पूर्ति करने का आश्वासन शासक दल ने दिया था। उस अपने मांग-पत्र के बारे में शेष जनता के साथ बैंक कर्मचारी भी श्री चह्वाण को पूछ रहे हैं ऐसे समय अर्थ मन्त्री ने ही जनता के मांग-पत्र की बात 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे' वाली श्रेणी की है। मालूम होता है कि सरकार को यह विश्वास है कि अभी तक दिए हुए आश्वासन वे पूरे नहीं कर सकते और इसके कारण सरकार खोज रही है कि अपनी असफलता का उत्तरदायित्व या दोष किस पर डाला जाए। वह बहाने की खोज में है। अब तक संसद में स्पष्ट बहुमत न होने के कारण अपनी असफलताओं के लिए अन्य दल तथा नेताओं को स्केप गोट बनाना आसान था। किन्तु अब स्पष्ट बहुमत होने के कारण इस तरह की बहाने बाजी नहीं चल सकती। इसलिए अपनी असफलता का दोष जिनके माथे थोपा जा सकता है ऐसे बलि के बकरों की खोज सरकार कर रही है। इस प्रक्रिया में बैंक कर्मचारी को ही उन्हों ने सब से पहले पकड़ लिया है। वास्तव में आर्थिक क्षेत्र में आने वाली असफलता का कारण स्वयं सरकार तथा उनकी गलत नीतियां ही हैं। आर्थिक नारे देना यह एक बात है और राष्ट्र का पुनर्निर्माण यह दूसरी। दूसरे कार्य में सफल होना इनके बस की बात नहीं। अत: सरकार की यह चाल हमें समझनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिये ताकि आर्थिक क्षेत्र की असफलता में जनता के मन में सम्भ्रम निर्माण करने में सरकार सफल न हो सके।

वैसे तो राष्ट्रवादी श्रमिक के नाते हम देश के पुनर्निर्माण के लिये चाहे जितना काम करने और स्वार्थ त्याग करने को तैयार हैं किन्तु हमें यह भरोसा होना चाहिये कि यह त्याग देश के लिये वास्तव में उपयुक्त है। केवल आकर्षक नारों से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम यह देखना चाहते हैं कि घोषित आदर्श प्राप्ति के लिये आवश्यक वास्तविकतावादी नीति सरकार अपना रही है और इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक

संगठन-यन्त्र सरकार के पास है। इन दोनों बातों में स्थिति निराशाजनक सी ही है।

आकर्षक योजनाओं के बावजूद यह सत्य है कि अधिकतर उत्पादन तथा समानान्तर वितरण के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने की कोई भी व्यावहारिक योजना सरकार के पास नहीं है। इसके कई उदाहरण हर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं। केवल उदाहरण के लिए सरकार की घोषित भूमि नीति का ही विचार करें। भूमि सुधार के नियम विभिन्न राज्यों में आ गए हैं। फिर भी चर्चायें चल रही हैं कि क्या सीलिंग और छोटा किया जाए। शासक दल में ही इस विषय में दो राय हैं। एक राय यह है कि सीलिंग और छोटा किया तो अलाभकारी (uneconomic holdings) की संख्या तथा विस्तार बढ़ जाएगा और वह हमारी अर्थनीति पर बड़ा बोझ होगा। इसके अलावा सीलिंग कितना भी छोटा किया तो भी ग्रामीण विभागों के सभी भूमिहीन लोगों को हम भूमि दे सकेंगे, यह सम्भव नहीं। दूसरी राय यह है कि सीलिंग छोटा करना यह समाजवाद की मांग है। गैरलाभकारी इकाइयों को लाभकारी बनाने के विषय में विचार किया जा सकता है। किन्तु सर्वप्रथम सीलिंग छोटा किया जाए और अतिरिक्त भूमि का बटवारा किया जाए। यह दूसरी राय रखने वाले आदर्शवादी लोग किताबी समाजवाद के कारण इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। किन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में अलाभकारी खेत की समस्या का हल कैसे निकाला जाए इसका कोई भी स्पष्ट उत्तर उनके पास नहीं है। हमारे अलाभकारी खेत प्रायः बिखरे हुये हैं, एक दूसरे से सटे हुये नहीं हैं।

मेरे कहने का मतलब यह कदापि नहीं कि सीलिंग छोटा न हो, किन्तु उसके फलस्वरूप निर्माण होने वाली समस्याओं का हल न निकालते हुये केवल किताब का आधार ले कर घोषणा करना ठीक नहीं। मिश्र में आसवान बांध पूरा होने के पश्चात उससे लाभान्वित भूमि का बटवारा छोटे-छोटे अलाभकारी खेतों में किया गया किन्तु यह सभी खेत

एक दूसरे से सटे हुए थे। इसके कारण अलग खेतों के स्वामित्व के अधिकार अलग २ भूमि-हीनों को देने के बाद भी सर्विस कोआपरेटिव के द्वारा अलाभकारी जोत को लाभकारी बना दिया। हमारे देश में अलाभकारी खेत बिखरे हुये होने के कारण सर्विस कोआपरेटिव के माध्यम का ठीक उपयोग हम नहीं कर सकते और इस कारण इन खेतों को लाभकारी बनाना भी हमारे लिये सम्भव नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्या इस कठिनाई से हमारे लिये और कोई रास्ता नहीं ? ऐसी बात नहीं है। हर गांव के क्षेत्र में हम जमीन की दोबारा चकबन्दी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से बिखरे हुये अलाभकारी खेतों को एक दूसरे से सटा हुआ बना सकते हैं। इसके कारण जिनकी जमीन लेनी पड़ेगी उनको मुआवजा भी हिसाब से दिया जा सकता है। मुआवजे के रूप में उसी क्षेत्र की दूसरी जमीन भी दी जा सकती है। किन्तु इस प्रकार अलाभकारी जोत एक दूसरे से सटे हुए रहें तो सर्विस कोआपरेटिव का पूरा उपयोग करते हुये उन सब को लाभकारी बना सकते हैं।

स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई रचनात्मक विचार हमारे शौकिया समाजवादी लोगों के पास नहीं है। वे इस लिए नारा लगा रहे हैं क्योंकि उनकी जीविका किताब में ही है। इस प्रकार का पुस्तकीय दृष्टिकोण या पाठ्यक्रमीय समाजवाद (Textbook Socialisam) हमारी सरकार का है। यह धारणा सभी बुद्धिमान लोगों की है।

नीतियां अच्छी रहीं तो भी उनको कार्यान्वित करने के लिए संगठन की मशीनरी हर स्तर पर आवश्यक है। राष्ट्र का आर्थिक पुनर्निर्माण केवल नौकरशाही के भरोसे नहीं हो सकता यहां तक कि तानाशाही भी केवल नौकरशाही के भरोसे नहीं लायी जा सकती। लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ इसी के आधार पर पार्टी मशीनरी के आधार पर नौकरशाही के माध्य से यदि कोई तानाशाही लाना चाहेगा तो वह नौकरशाही का बन्दी बन कर रहेगा। वही बात राष्ट्रनिर्माण की है। इस कार्य के लिए जो आदर्श-

वादिता और लग्न चाहिये वह नौकरशाही में नहीं पायी जाती। संसार में जहां-जहां क्रान्ति हुई और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हुआ वहां-वहां यह देखा गया कि क्रान्तिवादी नेताओं के पास सभी स्तरों पर काम करने वाली उनकी अपनी पार्टी मशीनरी है, आदर्शवादी कार्यकर्त्ताओं के गुट हैं। यह गुट नौकरशाही पर दबाव ला कर उनसे काम ले सकते हैं और वह सम्भव न हुआ तो नौकरशाही को हटा कर प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्था भी वे निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यकर्त्ताओं की संख्या कम रही तो भी चलेगा किन्तु हर स्तर पर उनका गुट प्रभावी होना चाहिए। नौकरशाही ने साथ दिया तो उसके सहयोग से, और उसने विरोध किया तो उसको ठुकराते हुए यह गुट का जाल पूर्वनियोजित रूप से राष्ट्र निर्माण का कार्य पूरा करेगा।

यह बात स्पष्ट है कि इस तरह की पार्टी मशीनरी विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्त्ताओं के गुट का फैला हुआ जाल हमारे प्रधानमन्त्री या सत्तारूढ़ दल के पास आज नहीं है। कारण भी स्पष्ट है। श्री एम० एन० राय ने कहा कि क्रान्ति पूर्वकाल खण्ड में जगह-जगह लड़ाकू क्रान्ति वीरों के सक्रिय गुट निर्माण होते हैं, वे लढ़ने का काम करते रहते हैं, युद्ध और युद्धकाल की शिक्षा दोनों साथ-साथ चलते रहते हैं। और इस प्रकार क्रान्ति कार्य में उन्हें जो अनुभव प्राप्त होता है, उनके अन्दर जिन गुणों का विकास होता है उनके कारण क्रान्ति उत्तरकाल खंड में यह कार्यकर्त्तिओं के गुट ही अपने-अपने विभाग में तथा स्तर पर प्रशासन का काम संभाल लेते हैं। इसके लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास तथा जनता का विश्वास, दोनों की सिद्धि क्रांतियुद्ध के काल में ही हो जाती है। श्री राय का यह प्रतिपादन विभिन्न क्रांतियों के अनुभव पर आधारित है।

लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के बाद भी श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास इस प्रकार के संगठन की मशीनरी नहीं है। यह सर्वविदित है। क्योंकि श्री राय ने जिस प्रकार के क्रांति युग की कल्पना की थी उस

प्रकार का युद्ध छेड़ते हुए भी हमें इन्डियन इनडिपेंडेंस एक्ट, १९४७ के अंतर्गत स्वराज्य की प्राप्ति हुई। फलत: इसी प्रकार के संगठन का अभाव सत्तारूढ़ दल के लिए स्वाभाविक है क्योंकि सत्ता के हस्तांतरण के पश्चात दल के मूल्यों में परिवर्तन आया, त्याग पर आधारित राष्ट्रनिर्माण के ध्येय का स्थान भोग पर आधारित सत्ता सम्पादन ने लिया, और क्रांतिकारी मनोवृत्ति का स्थान अवसर-वादिता ने लिया। नव-निर्माण का महान कार्य इस मशीनरी के माध्यम से होगा, यह आशा व्यर्थ है। चूहों के कंधों पर बन्दूकें देकर महान युद्ध जीता नहीं जा सकता। इस प्रकार की संगठन की मशीनरी श्रीमती गांधी के पास नहीं अत: अपने ही दल के भरोसे क्रांति लाने का उनका विचार मृग-मरीचिका के समान है।

उनके सामने दो विकल्प हैं। या तो दलगत अहंकार की शिकार बन कर निर्माण कार्य में असफलता स्वीकार करें या दलगत अहंकार को छोड़ कर राष्ट्रवादी कार्यकर्त्ताओं के गुट स्थान-स्थान पर निर्माण करने वाले देशव्यापी संगठन विश्वास में लेकर उसके माध्यम से पुनर्रचना का कार्य पूरा करे। इस प्रकार का गैरराजनीतिक स्तर पर काम करने वाला कट्टर राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी संगठन देश में आज भी विद्यमान है। जहां तक मज़दूर क्षेत्र के सम्बन्ध में इस देश में आदर्शवादी कार्यकर्त्ताओं का गुट हर स्तर पर तथा हर उद्योग-सेवा में निर्माण करने का श्रेय भारतीय मज़दूर संघ को ही है। राजनैतिक स्वार्थ से ऊपर उठते हुए केवल राष्ट्र निर्माण का विचार सरकार ने सामने रखा तो इस कार्य में पूरा सहयोग देने की सिद्धता भारतीय मज़दूर संघ की है किन्तु हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे कार्य का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए ही किया जा रहा है न कि व्यक्तिगत या दलगत स्वार्थ के लिए।

भारतीय मज़दूर संघ ने प्रारम्भ से ही सुझाव दिया है कि स्वायत्त मुद्रा सत्ता (autonomous monotary authority) का निर्माण किया जाए, उसके लिये रिज़र्व बैंक की रचना तथा स्वरूप में

उचित परिवर्तन लाये जायें, मुद्रा नियंत्रण के माध्यम से मूल्य नियन्त्रन तथा क्रैडिट पालिसी के माध्यम से पूर्ण रोजगारी द्विविध उद्देश्य उस अथार्टी के रखे जायें, एक-एक परिवार तथा गांव की लघु योजना बना कर उसे कार्यान्वित करते हुए आज के अविश्वसनीय लोगों को विश्वसनीय बनाने के हेतु देश-व्यापी फाइनेन्सियल कन्सलटेशन सर्विस का निर्माण किया जाये, आदि सुझाव हमने कई बार दिये हुये हैं। देश की अर्थनीति में बैंकिंग का वही स्थान है जो कि देश की शान्ति सुरक्षा व्यवस्था में रेलवे का है। शान्ति सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे यह देश की जीवन रेखा है तो अर्थ रचना की दृष्टि से बैंकिंग यह देश की जीवन रेखा है। इसको सफल बनाना कर्मचारियों के सहयोग से ही सम्भव है। फाइनैन्सियल कन्सलटेशन सर्विस को व्यावहारिक रूप देना यह बैंक कर्मचारियों के द्वारा ही हो सकता है। और उसके ऊपर देश का आर्थिक भविश्य निर्भर है। यह कार्य करने के लिए बैंक कर्मचारियों को प्रवित्त करना तथा उन्हें सक्षम बनाना यह काम एन० ओ० बी० डब्ल्यू० के जैसी राष्ट्रवादी, रचनात्मक संस्था ही कर सकती है। सस्ती लोकप्रियता के पीछे लगे हुए नेताओं की संख्या यह रचनात्मक कार्य नहीं कर सकती। राष्ट्र निर्माण की लड़ाई में राष्ट्र की सेना का सब से अगुआ पथिक यानि बैंक कर्मचारी ही है। और इस भूमिका का निर्वाह करने की क्षमता उनके अन्दर निर्माण करना यह कार्य भारतीय मज़दूर संघ ही कर सकता है।

इस परिस्थिति में हमारा कर्त्तव्य स्पष्ट है। हम किसी की प्रमाणिकता पर संदेह नहीं करते किन्तु यह प्रमाणिकता अपने विचार तथा अचार से प्रस्थापित करना यह जिम्मेदारी सरकार की ही है। यह बात उन्होंने सिद्ध कर दी तो राष्ट्र निर्माण के कार्य में उनके साथ सहयोग करने के लिए भारतीय मज़दूर संघ सदा ही तैयार है। किन्तु मज़दूर वर्ग के हित को अगर वह सिद्ध न कर पाए और निर्वाचन पूर्व आश्वासन केवल चालबाजी मात्र दिखाई दिए तो सरकार से संघर्ष करते हुए अपनी बातें मनवाने के

लिए भारतीय मज़दूर संघ नित्य सिद्ध रहेगा। यही हमारी भूमिका है। हम राजनैतिक झंझट में जाना नहीं चाहते। जहां एक ओर अपने जायज़ अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम संघर्षक्षम हैं वहां दूसरी ओर राष्ट्र निर्माण कार्य के लिए हम समन्वयक्षम तथा सहयोगक्षम भी हैं। मतलब यह है कि हमारी नीति उत्तरदायित्व पूर्ण सहयोग और प्रतियोगी सहयोगिता की है। एक राष्ट्रवादी श्रमिक संस्था के नाते हम इसी भूमिका को ही ले सकते हैं।

यह सब बातें ध्यान में रखते हुए हम धीरज के साथ आगामी भविष्य काल में सरकारी नीति के निर्धारण के विषय में सतर्क रहें और उनकी नीति को देख कर हमारा पग हम निश्चित करें।

साथ ही साथ एक अपरिहार्य बात भी ध्यान में रखें। सरकारी नीतियां गलत रहीं तो उनका विरोध करने के लिए हमारी संगठित शक्ति का निर्माण आवश्यक है। वे नीतियां उचित रहीं तो भी उनको कार्यान्वित कराने के लिए हमारी प्रबल संगठन शक्ति की आवश्यकता है। दोनों परिस्थितियों में हमारी सफलता हमारी शक्ति पर ही निर्भर रहेगी। अतः चारों ओर की परिस्थितियों के विषय में सतर्क सावधान रहते हुए विविध कठिनाइयों के बावजूद हम अपना संगठन शीघ्र ही बलवान बनायें यही आवश्यक है। इसी माध्यम से राष्ट्र पुनःनिर्माण में हमारा सहयोग लिया जा सकता है।

देश आज दोराहे पर खड़ा है। निकट भविष्य मे उसके भाग्य का निर्णय होने वाला है। उसे पराए राष्ट्रों का गुलाम बनाने के लिए हमारे ही कुछ भाई जयचन्द और मानसिंह बन कर प्रयास चला रहे हैं। चारों ओर असंतोष तथा विफलता का वायुमंडल है। अनुचित ढग से विस्फोट आ तो देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इस संकटमय परिस्थिति में आर्थिक क्षेत्र की कठिनाइयों से मुकाबला करते हुए पुनः आर्थिक निर्माण सफल बनाने की सबसे अधिक जिम्मेदारी बैंक कर्मचारियों की ही है। देश को वर्ग बैंकिंग (Class Banking) से सामूहिक बैंकिंग (Mass Banking) तक लेजाना हमारा ही कर्त्तव्य है। यह जानकारी चन्डीगढ़ अधिवेशन का संदेश लेकर हम यहां से अपने अपने-स्थान पर वापस जायें यही अभिप्रेत है।